Dyuo - UCC/1183
18.7.14

# MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

(A State University established under Haryana Act No. XXV of 1975)

**'A' Grade University Accredited by NAAC**

## ESTABLISHMENT BRANCH

## OFFICE ORDERS

The Vice-Chancellor, in anticipation of the approval of the Executive Council has approved to implement the Regularization Policy for Group C and D employees/workers issued by the State Government vide letter No. 6/7/2014-IGSI dated 20.06.2014.

**REGISTRAR**

**Endst. No. EN-6/2014/P-495/**.11594-607 **Dated** 10-07-2014

A copy of the above alongwith the State Government letter No. 6/7/2014-IGSI dated 20.06.2014 and a copy of the orders of the Vice-Chancellor, are forwarded to the following for information and taking further necessary action:-

1. ✓ The Director, University Computer Centre, M.D. University, Rohtak
2. The Finance Officer, M.D. University, Rohtak.
3. The Joint Director (Audit), M.D. University, Rohtak.
4. All set Incharges of Estt. (N.T.) Branch, M.D, University, Rohtak and EN-4 set is requested to refer the matter to the Executive Council for approval.

**Deputy Registrar (Estt.) N.T.**
**For Register**

upload in Notices section.

JDEW

-135-

F.P.P.

## M.D. University, Rohtak

**Reference orders of the Vice-Chancellor on pre-page:**

In this connection, it is submitted that the regularization policy for Group C and D employees/workers circulated by the office of Chief Secretary to Government of Haryana vide letter No. 6/7/2014-IGSI dated 20.06.2014 has been downloaded from the website of State Government. A copy of the same may be perused at **Flag 'A'**. It is also submitted that the said policy is addressed to All the Registrars of the Universities in the State, but the same has not been received officially in the University. However, for implementation the said regularization policy, it requires the approval of the Executive Council.

Hence, in view of the position explained above and orders of the Vice-Chancellor on pre-page, if agreed to, the case is submitted to the authorities for orders:-

Whether the authority would like to refer the same to the Executive Council by the concerned set of Establishment Branch

OR

We may wait for officially receipt of the said regularization policy.

Case is submitted for orders, please.

Surender Kumar
Clerk 20/6/14
EN-6

Supdt (Estt.)

20/6/14
(GHANSHYAM ...)

DR(Estt)

The case may kindly be submitted to the Vice-Chancellor for orders whether he would like to approve the policy at 'A' in anticipation of the approval of the EC or would like to refer the same to EC. Thereafter the cases will be examined individually in the light of the policy received from the State Govt.

27/6/14

Registrar

The proposal at 'A' above is submitted for consideration and approval.

27.6.14
(S.P. VATS)
REGISTRAR

V.C.

30/6/14
(H.S. CHAHAL)
V.C.

Registrar

30.6.14

Ro-5079 27/6/14 30/6/14

EN-6/421 26-6-14

E-2058 27/6/14 1/7/14

VC 4854 27/6/14 30/6/14

SE-I 1/7/14

EN-6

Supdt-II 1/7/14 Dr (Estt)/NS 1/7/14

Government of Haryana
General Administration Department
General Services-I Branch

No. 6/7/2014-IGS I                                        Dated 20. 06. 2014

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana.
2. All Heads of Departments, Commissioners, Ambala , Hisar, Rohtak and Gurgaon Divisions.
3. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
4. All the Registrars of the Universities in the State.

**Subject: - Amendment/framing of Regularization Policy for Group C and D employees/workers.**

........

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above to enclose a copy each of the notifications bearing no. 6/7/2014-1GS1 dated 18.06.2014 regarding regularization of services of Group 'C' and Group 'D' employees/workers appointed/engaged on contract basis as well as regularization of the services of left over cases for Group 'C' and 'D' employees under the policies dated 17.6.1997, 5.11.1999, 1.10.2003 , 10.2.2004 and instructions dated 7.3.1996 read with 18.3.1996 which were rescinded vide Government notification dated 13.4.2007 issued vide letter No. 43/31/2006-1GS1, dated 25.4.2007 and 29.5.2007 for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

Parmod Kumar
Superintendent General Services-1,
for Chief Secretary to Government Haryana.

Endst.No. 6/7/2014-1GSI                                        Dated 20 June, 2014

1. A copy is forwarded to the Secretary, Haryana Staff Selection Commission, Panchkula for information and necessary action.

2. A copy each of each notification are forwarded to State Informatics Officer, National Informatics Centre, Haryana for hosting on the State website.

Parmod Kumar
Superintendent General Services-I
for Chief Secretary to Government Haryana.

Regd. No. CHD/0093/2012–2014

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, JUNE 18, 2014 (JYAISTHA 28, 1936 SAKA)

### हरियाणा सरकार

### सामान्य प्रशासन विभाग

### (सामान्य सेवाएं-I)

### अधिसूचना

दिनांक 18 जून, 2014

क्रमांक 6/7/2014-1जी०एस०I.—हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 के खण्ड 6 के परन्तुक के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्रुप ग के ऐसे पदों को, जो अनुबन्ध आधार पर ग्रुप ग कर्मचारियों/कर्मकारों द्वारा 28 मई, 2014 को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण किए गए हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से तथा ग्रुप घ पद सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाले जाने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं।

1. सरकार द्वारा/राज्य सरकार की अनुमोदित ऐजन्सी द्वारा अनुबन्ध आधार पर लगे हुए ग्रुप ग और ग्रुप घ कर्मचारियों/कर्मकारों की सेवाएं नियमित की जाएंगी यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, अर्थात् :-

   (i) कि ऐसा कर्मचारी/कर्मकार जिसने 28 मई, 2014 को कम से कम तीन वर्ष के लिए कार्य किया हो और अब भी सेवा में हो।

   (ii) कि कर्मचारी/कर्मकार नियुक्ति/नियोजन की तिथि को पद के लिए विहित योग्यताएं रखता हो।

(iii) कि पद जिसके विरुद्ध नियमित किया जाना है प्रारम्भिक नियुक्ति/नियोजन के समय और नियमन के समय भी रिक्त पद स्वीकृत होना चाहिए।

(iv) कि समय-समय पर जारी की गई आरक्षण पॉलिसी भी नियमन के समय ध्यान में रखी जाएगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग के लिए बना रोस्टर सामान्य या अन्य प्रवर्ग द्वारा भोगा गया है, तो अगली रिक्त उक्त आरक्षित प्रवर्ग या परस्पर अदला-बदली से भरा जाना चाहिए।

(v) कि ऐसे कर्मचारी/कर्मकार का कार्य और आचरण सन्तोषजनक होना चाहिए।

(vi) कि अंशदायी पेंशन स्कीम सेवा के नियमन के बाद लागू की जाएगी।

(vii) कि अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा उपयुक्त प्रमाण-पत्र तथा जन्म-तिथि का दस्तावेजी सबूत सम्बन्धी कर्मचारी/कर्मकार से लिया जाएगा।

(viii) कि सरकारी अनुदेशों के अनुसार उसका/उसकी पूर्ववरित पुलिस विभाग द्वारा सत्यापित करवाया जाएगा यदि यह पहले सत्यापित नहीं करवाया गया है।

(ix) कि ऊपर अधिकथित मानदण्ड में कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

2. ऐसे पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यक्षेत्र से, इसके द्वारा, बाहर निकाले जाते हैं।

3. इस प्रकार नियमित किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमन की तिथि से नियत की जाएगी और इन कर्मचारियों की नियमन की तिथि से पूर्व नियमन आधार पर अन्तिम नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता में नीचे रखे जाएंगे। तथापि, ऐसे कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता अनुबन्ध आधार पर उनके पद ग्रहण करने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यदि ऐसे कर्मचारियों के अनुबन्ध आधार पर पद ग्रहण करने की तिथि एक समान है, तब आयु में बड़ा कर्मचारी आयु में छोटे कर्मचारी से वरिष्ठ होगा।

4. चूंकि यह पॉलिसी लोकोपकारी आधार पर एकमुश्त उपाय है। कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा, यदि इन अनुदेशों में वर्णित शर्तों को पूरा न करने के कारण अनुपयुक्त होगा।

5. भविष्य में तदर्थ/अनुबन्ध आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई भी गैरकानूनी/अनियमित नियुक्ति/नियोजन नहीं किया जाएगा।

6. आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग पूर्वानुमानित रिक्ति को हिसाब में लेते हुए रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी मांगें भेजेंगे और विज्ञापन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे कर्मचारियों के नियमन के परिणामस्वरूप विभागों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/ सामान्य प्रशासन विभाग को पहले से भेजी गई मांग प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी विभागों से अनुरोध है कि वह अभिनिश्चित करें कि उन कर्मचारियों की सेवाओं के नियमन से क्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई रिक्तियां परिवर्तित हो गई हैं, यदि हां, तो सम्बद्ध विभाग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग से इस सम्बन्ध में एक सप्ताह की अवधि के भीतर शुद्धि-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करेगा।

एस० सी० चौधरी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT**

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES-I)

**Notification**

The 18th June, 2014

**No. 6/7/2014-1G.S.I.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the proviso to clause 6 of the Haryana Government, General Administration Department (General Services), Notification No. 523-3GS-70/2068, dated 28th January, 1970, the Governor of Haryana hereby specifies such Group-C posts, as have been held for a minimum period of three years as on 28th May, 2014, by Group-C employees/ workers on Contract basis is to be taken out of the purview of the Haryana Staff Selection Commission and Group D posts from the purview of competent authority.

The services of Group C and Group D employees/workers engaged on contract basis engaged by Government/ approved agency of the State Government be regularized if they fulfil the following conditions, namely:—

(i) That the employee/worker should have worked for not less than 3 (three) years as on 28th May, 2014 and is still in service.

(ii) That the employee/worker possessed the prescribed qualifications for the post on the date of appointment/ engagement.

(iii) That the post against which the regularization is to be done should be a sactioned vacant post at the time of initial appointment/engagement and also at the time of regularization.

(iv) The reservation policy issued from time to time may also be kept in view at the time of regularization. In case the roster meant for reserved category is consumed by General or other category, the next vacancy should be filled up from the said reserved category or vice versa.

(v) That the work and conduct of such employee/worker should have been satisfactory.

(vi) The contributory pension scheme would be applicable after regularization of the service.

(vii) A medical fitness certificate and documentary proof of Date of Birth as per the instructions shall be obtained from the employee/worker concerned.

(viii) His/her antecedents should be got verified by the Police Department as per the Government instructions if it was not done earlier.

(ix) No relaxation in the criteria as liad down above shall be allowed.

**2.** Such posts are hereby taken out of the purview of the Haryana Staff Selection Commission or competent authority, as the case may be.

**3.** The seniority of the employees so regularized shall be fixed from the date of their regularization and they shall be placed below in the seniority to the employees last appointed on the regular basis before the date of regularization of these employees. However, the *inter-se-seniority* of such employees shall be determined in accordance with the date of their joining the post on contract basis. If the date of joining the post on contract basis of such employees is the same, then the older employee shall rank senior to the employee younger in age.

**4.** Since this policy is a 'one time measure' on humanitarian ground, no person shall be entitled to claim it as a matter of right, if found unsuitable due to non fulfillment of the conditions mentioned in these instructions.

**5.** In future, no **illegal/irregular** appointment/employment on adhoc/contract basis shall be made against the sanctioned posts.

**6.** Further, it is also clarified that the departments might have sent their requisitions to fill up the vacant posts by taking into account the anticipated vacancy and advertisements may have also been issued by the Haryana Staff Selection Commission/General Administration Department and as a result of regularization of such employees, the number of available vacancies in the departments may change and affect the requisitions already sent to Haryana Staff Selection Commission/General Administration Department. Therefore, all the Departments are requested to ascertain that by regularizing the serivces of their employees, whether the number of vacancies requisitioned to HSSC/GAD have changed. If yes, the Department concerned shall request the HSSC/GAD within a period of one week to issue corrigendum, in this regard.

S. C. CHOUDHARY,
Chief Secretary to Government Haryana.

**HARYANA GOVERNMENT**

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES-I)

**Notification**

The 18th June, 2014

**No. 6/7/2014-1G.S.I.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the proviso to clause 6 of the Haryana Government, General Administration Department (General Services), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, General Administration Department (General Services-I), Notification No. G.S.R. 13/Const./Art. 309/2007, dated 13th April, 2007, namely :—

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, General Administration Department (General Services-I), Notification No. G.S.R. 13/Const./Art. 309/2007, dated 13th April, 2007 the following proviso shall be added at the end, namely :—

"Provided that the left over Group "C" and "D" employees working on adhoc/contract/daily wages/work-charged basis, who could not be regularized under the regularization policy issued *vide* notifications mentioned at serial No. 1 to 4 above due to administrative reasons but were otherwise eligible, shall be regularized with effect from the date(s) they were eligible for regularization".

S. C. CHOUDHARY,
Chief Secretary to Government Haryana.

**हरियाणा सरकार**

सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं-I)

**अधिसूचना**

दिनांक 18 जून, 2014

**क्रमांक 6/7/2014-1जी०एस०I.**—हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523-3जी०एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 के खण्ड 6 के परन्तुक के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं-I), अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 13/संवि०/अनु० 309/2007, दिनांक 13 अप्रैल, 2007 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं-I), अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 13/संवि०/अनु० 309/2007, दिनांक 13 अप्रैल, 2007 में, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु तदर्थ/अनुबन्ध/दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज आधार पर, कार्यरत रह गए ग्रुप ग तथा घ कर्मचारी जो उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 पर वर्णित अधिसूचना द्वारा जारी नियमित पॉलिसी के अधीन प्रशासकीय कारणों से नियमित नहीं किए जा सकते थे किन्तु अन्यथा पात्र थे वे ऐसी तिथि, जिसको वे नियमित करने हेतु पात्र थे, से नियमित किए जाएंगे।"।

एस० सी० चौधरी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।